भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2648

दिनांक 04.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाई-स्पीड इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना

2648. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फरवरी 2026 तक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए स्वीकृत 2,000 हाई-स्पीड चार्जिंग स्टेशनों के स्थलों को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में इन चार्जरों की स्थापना के लिए शत-प्रतिशत पूंजीगत अनुदान प्रदान कर रही है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी ईवी ब्रांड में अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए इन चार्जिंग स्टेशनों को "ओपन चार्जिंग प्वाइंट प्रोटोकॉल" (ओसीपीपी) से युक्त किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार इन हाई-स्पीड चार्जिंग हब के लिए समर्पित हरित-ऊर्जा फीडरों को सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय के साथ सहयोग कर रही है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इस अवसंरचना विस्तार के परिणामस्वरूप लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक भारी वाहनों और यात्री कारों की बिक्री में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत, प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों सहित देशभर में पर्याप्त संख्या में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना हेतु 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई विशेष लक्षित संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

(ख): पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत, 100% पूंजीगत अनुदान केवल “श्रेणी-क” स्थानों के लिए प्रदान किया जाता है, जिनमें सरकारी कार्यालय, सरकारी आवासीय परिसर तथा

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के परिसर सम्मिलित हैं, बशर्ते कि इन स्थानों पर ईवी चार्जिंग के लिए आम जनता की निर्बाध पहुंच उपलब्ध हो।

(ग): सभी ब्रांडों के इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ व्यापक अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत वित्तपोषित ईवी चार्जिंग स्टेशनों में ओपन चार्ज प्वाइंट प्रोटोकॉल (ओसीपीपी) की सुविधा उपलब्ध होती है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ): जी हां। वर्ष 2019-20 से 2025-26 की अवधि के दौरान ईवी की बिक्री में निरंतर वृद्धि का रुझान देखा गया है तथा ईवी की समग्र पैठ वर्ष 2019-20 के 0.68% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 8.26% हो गई है। तथापि, ईवी चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना तथा ईवी की बिक्री में हुई वृद्धि के मध्य प्रत्यक्ष कारणात्मक संबंध स्थापित करने के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा कोई आकलन नहीं किया गया है।

******